

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

स्व-सहायता समूह से बहनों के जीवन में नए सूर्य का हुआ उदय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री कुक्षी में स्व-सहायता समूह सम्मेलन सह-पोषण पखवाड़े कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल,ब्यूरो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्व-सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की पहल में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। सशक्त नारी ही समृद्ध प्रदेश का आधार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को धार जिले के कुक्षी में आयोजित स्व-सहायता समूह सम्मेलन सह-पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की बहनों को निकाय चुनाव में 50व आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 2029 तक लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33व आरक्षण के प्रयास भी किये जा रहे हैं। जमीन



या मकान की रजिस्ट्री महिला के नाम पर करने पर पंजीयन शुल्क में छूट दी जा रही है। लाड़ली बहना योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। महिला स्व-सहायता समूह की बहनों ने हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर अपना सामर्थ्य दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

आराधना की जाती है। दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है, जो राष्ट्र को माता मानता है। राज्य सरकार हर माह लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए डालकर रक्षाबंधन मना रही है। सभी पात्र लाड़ली बहनों को 1250 रुपए की राशि मिलती रहेगी। अगर बहनों के हाथों में पैसे आएंगे तो परिवार में कुछ बचत होगी। सरकार बहन-बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह परिवार और समाज को सशक्त बनाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। प्रदेश के हर घर को गोकुल बनाएंगे। राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से नई गौपालन योजना बनाई गई है। भविष्य में गौशालाओं के माध्यम से प्रदेश की बहनों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। राज्य सरकार उन्हें नए व्यवसाय से जोड़ने के कार्य कर रही है।

निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

ग्वालियर,नर्स।। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने विभागीय कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त श्री विजय राज, श्री मुनीश सिंह सिकरवार, अपर आयुक्त वित्त श्रीमती रजनी शुक्ला, उपायुक्त श्री अमर सत्य गुप्ता, अधीक्षण यंत्री श्री जेपी पारा, कार्यपालन यंत्री श्री संजीव गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की मार्च माह के साथ ही अप्रैल माह की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही निर्देशित किया कि अधिकारी ज्यादा शिकायतें लबित है उनको नोटिस जारी किया जाए। संबंधित अधिकारी एल-1 अधिकारी की शिकायतों का रिस्कु सप्ताह में दो बार करें जिससे सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली समस्याओं का निराकरण संतुष्टि के साथ समय पर किया जा सके। निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने सीवर, साफ सफाई एवं



आवारा धानों की अधिक शिकायत मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान में तेजी लाएं तथा प्रतिदिन कम से कम 25 धानों को पकड़ा जाए और वैकसीनेशन एवं बंध्याकरण किया जाए। इसके साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों के जवाब समय सीमा में दिए जाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के पत्रों को लेकर भी निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों के आने वाले पत्रों के जवाब लिखित में संतुष्टि के साथ दिया जाए। निगमायुक्त ने बैठक के दौरान समग्र आईडी की ईकेवायसी में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने गर्मी को देखते हुए प्याऊ लगाने के

निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही निर्देशित किया कि जहां भी अबैध धुलाई सेंटर चला रहे हैं उन्हें तत्काल बंद करायें तथा शहर में आमजन को पानी का अपव्यय न करने के लिए जागरूक भी करें तथा शहर में जो वाटर एटीएम बंद है उसको ठीक कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में यह भी निर्देशित किया कि डस्टबिन को शहर के प्रमुख स्थानों पर लगायें तथा उनकी देखरेख भी करें। साथ ही शहर से निकलने वाले गोबर का उचित प्रबंधन किया जाए इसकी रूपरेखा बनाएं। इसके साथ ही अन्य कार्यों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कार्ययोजना के प्रावधानों से जन-जन तक पहुंचेगी परिषद: श्री नागर

भोपाल,ब्यूरो। संवाद योजानांतर्गत प्रदेश में स्वेच्छिकता के वातावरण को सुदृढ़ करने एवं विकास कार्यों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से म.प्र. जन अभियान परिषद की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना पर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुधवार को राज्य कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में परिषद की योजनाओं प्रस्प्टुटन, नवार्कुर, संवाद, दृष्टि, समृद्धि, विस्तार योजना के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हुई। परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर ने कहा कि कार्ययोजना के प्रावधानों से परिषद जन-जन तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रावधानों से भी अधिक आवश्यक है परिषद के मूल स्वेच्छिकता भाव को संपोषित कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में लगाना। उन्होंने जनभागीदारी से जन अभियानों को सफल करने में परिषद की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इससे परिषद को प्रतिष्ठा और पहचान दोनों मिल रही है। परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़ ने कहा कि नवार्कुर संस्थाओं का चयन स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। परिषद को ग्राम विकास प्रस्प्टुटन समितियों का क्षमता संवर्धन कर उनका चयन नवार्कुर संस्था के रूप में किये जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिषद के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पण का आग्रह करते हुए उन्होंने परिषद परिवार से प्रतिबद्धता, निष्ठा और पारदर्शिता से कार्य करने का आग्रह किया।

डीएम ने टैबलेट-स्मार्टफोन वितरण में लबित आवेदनों का निस्तारण करने के दिए निर्देश

पीएम इंटरनशिप योजना में बेरोजगार युवाओं का कशाय जाए पंजीकरण

अलीगढ़,ब्यूरो। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण के लंबित प्रकरणों के संबंध में विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने योजना के तहत आधार सत्यापन के लिए लंबित छात्रों को डिजि शक्ति पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु अभी भी 119 संस्थानों व विद्यालयों द्वारा 8213 छात्र-छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे जिले को प्राप्त टैबलेट्स व स्मार्ट फोन का वितरण संभव नहीं हो पा रहा है। डीएम ने सभी प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि छात्रों को लाभान्वित करने की इच्छा से कार्य करें। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कहा कि आगामी 10 दिन में लंबित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए पात्र छात्र-छात्राओं की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि छात्र-छात्राओं को टैबलेट्स व स्मार्ट फोन वितरण योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बैठक के दौरान सभी



विद्यालयों में पीएम इंटरनशिप योजना के तहत 21 से 24 आयु वर्ग वाले कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा 5000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह प्रदान करने के साथ ही शीर्ष कम्पनियों में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। बैठक में एडीएम वित्त मीनू राणा समेत विद्यालयों प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं संबंधित अधिकारियों उपस्थित रहे।

धौलपुर ब्यूरो। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में नियोजित श्रमिकों के कार्य समयावधि निर्धारण एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ग्रामी ऋतु में तापमान वृद्धि के दृष्टिगत श्रमिकों के कार्य निर्धारण किया जाता है। प्रभारी अधिकारी सहायता एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना ने बताया कि नियोजित श्रमिकों के आवश्यकतानुसार विश्राम काल रहित अवधि प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि आयुक्त नगर परिषद एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, सेपक एवं सरमथुरा को श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन तथा त् एवं ताप से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, महिला



गया। उन्होंने सभी परिवारों का यथा संभव समाधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जिससे अधिकतम परिवारी संतुष्ट हो सकें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला

क्षेत्र के भवनपुरा में विद्युत पोल एवं तारों को दुरस्त कराए जाने के संबंध में जेवीवीएनएल को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने परिवारी भूरी सिंह के खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना भी परिवारी को देना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी सुधारानी मीना सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

उचित मूल्य की दुकानों पर शेष पात्र परिवारों की हर हाल में 30 अप्रैल तक कराएं ई-केवायसी : कलेक्टर

ई-केवायसी न कराने वालों को नहीं मिलेगा राशन, कलेक्टर ने बैठक लेकर अभियान बतौर ई-केवायसी कराने के दिए निर्देश

ग्वालियर,नर्स।। उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिये ई-केवायसी अनिवार्य है, जो पात्रता पचीधारी उपभोक्ता 30 अप्रैल तक ई-केवायसी नहीं करायेंगे, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को सहीतौर पर बता दें कि वे 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी अवश्य करा लें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगम आयुक्त श्री



संघ प्रिय सहित जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ, खाद्य विभाग के अधिकारी एवं राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े अन्य अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एसडीएम अधीनस्थ अमले के माध्यम से अभियान बतौर ई-केवायसी का काम कराएं।

रेडक्रॉस इकाइयों के निर्वाचन की हो नियमित व्यवस्था : श्री पटेल

राज्यपाल ने की रेडक्रॉस की समीक्षा

भोपाल,ब्यूरो। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने प्रदेश की जिला रेडक्रॉस समितियों के निर्वाचन कार्य की राजभवन में समीक्षा की। उन्होंने जिला इकाइयों जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है अथवा हो गया है। उनके निवाचन की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भागव, कलेक्टर भोपाल श्री कौशलानंद विक्रम सिंह, राज्य रेडक्रॉस समिति के जनरल सेक्रेटरी



सहित राजभवन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि रेडक्रॉस की सभी स्तर की इकाइयों के निर्वाचन की नियमित

में है अथवा पूरा हो गया है। उनके निर्वाचन का कैलेंडर जारी किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने रेडक्रॉस से संबद्ध समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया को भी शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों से राजभवन द्वारा रेडक्रॉस इकाइयों को दिए गए अनुदान के उपयोग की समीक्षा करने की अपेक्षा की है। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को उचित औषधियों की उपलब्धता में बाधा नहीं आए। उन्होंने इस की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया है।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में नियोजित श्रमिकों के कार्य समयावधि प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की निर्धारित



गया। उन्होंने सभी परिवारों का यथा संभव समाधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जिससे अधिकतम परिवारी संतुष्ट हो सकें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला

क्षेत्र के भवनपुरा में विद्युत पोल एवं तारों को दुरस्त कराए जाने के संबंध में जेवीवीएनएल को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने परिवारी भूरी सिंह के खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलम्ब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें तथा उनके निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना भी परिवारी को देना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी सुधारानी मीना सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।



रामनरेश शर्मा बालकृष्ण शर्मा सटा. सरदार सिंह गुर्जर विजय जाहर सिंह शर्मा मोहर सिंह कंसाना अशोक शर्मा हड़वासी रामेश्वर सिंह गुर्जर राजेश शर्मा सिकरौदा दिलीप मिश्रा लाखन सिंह यादव छैरा लाखन सिंह यादव बिशगपुरा सूबे सिंह रावत राजपाल यादव मनोज मिश्रा अजीत गुर्जर अमन सिकरवार विनोद जादौन, बच्चू सिंह गुर्जर खसखड़ा करण सिंह यादव, रमेश उपाध्याय अरविंद कुशवाहा राजकुमार कुशवाहा किशोर शर्मा पुषेष्ट पाराशर रिकु सिकरवार निरंजन दुबे आशीष तोमर पप्पू गुर्जर मेवाड़ा, राजवीर बैसला, अंजय कटोर, मन्जु पचौरी राधा सिकरवार सपना जाटव सहित पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता शामिल थे।